केंद्रीय मंत्रीमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के दायरे में घोड़ों, खच्चरों और गधों को शामिल करने को मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता मे ंकेन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन मे ंऔर संशोधन को मंजूरी दे दीः

- घोड़ा, गधा व खच्चर के लिए उद्यमिता की स्थापना के लिए व्यक्तियों, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, एफसीओ और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- घोड़े और गधे के नस्ल संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी।
- केन्द्र सरकार घोड़े और गधे के वीर्य स्टेशन और न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 10 करोड़ देगी।
- चारा बीज प्रसंस्करण अव संरचना मे ंलगे उद्यमियो ंको 50 लाख तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स, एसएचजी, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी और किसान सहकारी समितियो ंको दी जाएगी। शेष परियोजना लागत की व्यवस्था लाभार्थियो ंद्वारा बैंक वित या स्व–पोषण के माध्यम से की जानी है।
- गैर–वन, बंजर भूमि, रेंज भूमि, गैर–कृषि योग्य और निम्नीकृत वन भूमि मेंचारे की खेती के लिए राज्य सरकारो ंको सहायता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य देश भर मे ंचारे की उपलब्धता बढ़ाना है।
- किसानों पर बोझ कम करने के लिए कार्य क्रम को सरल बनाया गया है। प्रीमियम का लाभार्थी हिस्सा घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है, केंद्र और राज्य शेष प्रीमियम को सभी राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात और कुछ राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात मे ंवहन करते हैं।

Union Cabinet approves inclusion of Horses, Mules and Donkeys under the ambit of National Livestock Mission

The Union Cabinet, under the leadership of Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has given the nod to further modifications of the National Livestock Mission (NLM), aimed at bolstering the livestock sector and promoting entrepreneurship in related activities. The approved modifications encompass a range of initiatives aimed at enhancing breed conservation, fodder seed processing infrastructure, fodder cultivation, and simplification of the Livestock Insurance Programme.

Key Modifications:

- **Entrepreneurship Development:** The inclusion of activities such as establishing entrepreneurship for horse, donkey and mule sectors. Individuals, FPOs, SHGs, JLGs, FCOs, and Section 8 companies will now receive a 50% capital subsidy up to 50 lakhs.
- Additionally, state governments will be supported for breed conservation of horses and donkeys
- The Central Government has allocated 10 crores for the establishment of semen stations and nucleus breeding farms for these animals.
- **Fodder Seed Processing Infrastructure:** Entrepreneurs engaged in fodder seed processing infrastructure will receive a 50% capital subsidy up to Rs. 50 lakhs. This subsidy will be extended to private companies, startups, SHGs, FPOs, FCOs, JLGs, and Farmers Cooperative Societies. The remaining project cost is to be arranged by beneficiaries through bank finance or self-funding.
- **Fodder Cultivation:** Support will be extended to state governments for fodder cultivation in non-forest, wasteland, range land, non-arable, and degraded forest lands. This initiative aims to increase fodder availability across the country.
- **Livestock Insurance Programme:** The programme has been simplified to reduce the burden on farmers. The beneficiary share of the premium has been reduced to 15%, with the Centre and State sharing the remaining premium at a ratio of 60:40 for all states and 90:10 for certain states.